परेशानी | रमजान में बिना विधुत के बिना परेशान हो रही जनता जिम्मेदार कौन?

धनपुरी-बुढार रोड पर मौत का खेल, 33 केवी लाइन लगाने में लापरवाही

नवभारत, धनपुरी/बुढार। धनपुरी-बुढार रोड इन दिनों विकास नहीं, बल्कि लापरवाही, भ्रष्ट मानसिकता और इंसानी जान की अनदेखी का खौफनाक उदाहरण बन चुका है। 33 केवी हाई टेंशन लाइन के विद्युतीकरण कार्य के नाम पर जो कुछ जमीन पर हो रहा है, वह किसी भी जिम्मेदार प्रशासन और व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। एक तरफ 13 मीटर ऊंचे पोलों पर बिना किसी सुरक्षा के मजदूरों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, तो दूसरी तरफ रमजान जैसे पवित्र महीने में घंटों बिजली गुल रहने से आम जनता बेहाल है। सवाल साफ है—क्या यहां विकास के नाम पर केवल बिल पास कराने और जेबें भरने का खेल चल रहा है?

नगर पालिका धनपुरी की निगरानी में चल रहे इस कार्य में सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मजदूरों को बिना सेफ्टी बेल्ट, बिना हेलमेट, बिना इंसुलेटेड ग्लव्स और बिना किसी प्रमाणित उपकरण के सिर्फ रस्सियों के सहारे 33 केवी के खतरनाक पोलों पर चढ़ाया जा रहा है। नीचे खड़े लोग सांस थामे इस खतरनाक मंजर को देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है—एक चूक और सब खत्म। लेकिन ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों को

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए यह सिर्फ 'काम जल्दी खत्म करो और भुगतान लो' का मामला बन चुका है।

विद्युत विशेषज्ञ बार-बार चेतावनी दे चुके हैं कि 33 केवी लाइन पर कार्य बिना शटडाउन, बिना अर्थिंग और बिना प्रशिक्षित सुपरविजन के करना सीधा-सीधा मौत को न्योता देना है। 'वर्क एट हाइट' के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट और प्रमाणित उपकरण अनिवार्य हैं, लेकिन यहां पुराने, प्रतिबंधित और खतरनाक तरीके अपनाए जा रहे हैं। यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित जोखिम है—जहां मजदूरों की जान को सस्ते में तौला जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। कोतमा, उमरिया और शहडोल में हाल ही में हुए हादसों ने पहले ही कई परिवारों को उजाड़ दिया है। इसके बावजूद धनपुरी में वही गलती दोहराई जा रही है। क्या प्रशासन को एक और लाश का इंतजार है? क्या हर हादसे के बाद केवल जांच समिति बनाकर फाइल बंद करना ही सिस्टम का तरीका बन चुका है? इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा आक्रोश जनता के बीच है। रमजान के पवित्र महीने में, जब लोगों को समय पर बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है—इफ्तार, सहरी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए—तब घंटों बिजली गायब रहती है। घरों में अंधेरा, पानी की किल्लत और गर्मी से बेहाल लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि यह समस्या 'तकनीकी' नहीं, बल्कि 'मिलीभगत' का नतीजा लगती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका धनपुरी, ठेकेदार और बिजली विभाग के कुछ अधिकारी मिलकर इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं। काम की गुणवत्ता, सुरक्षा और जनता की सुविधा को नजरअंदाज कर सिर्फ कागजों में सब कुछ सही दिखाया जा रहा है। मौके पर न तो कोई सुरक्षा इंतजाम है, न चेतावनी बोर्ड, न मेडिकल सहायता—और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी नजर आता है। जनता का गुस्सा अब उबाल पर है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोग मजबूर हैं। अगर वे विरोध करते हैं या काम रुकवाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें कानून और प्रशासनिक कार्रवाई का डर दिखाया जाता है। यही वजह है कि आक्रोश अंदर ही अंदर सुलग रहा है।

अब लोगों ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है— 'इस तरह की घोर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।' श्रम कानूनों के अनुसार, इस तरह के जोखिमपूर्ण कार्यों में सुरक्षा उपकरण देना, प्रशिक्षित मजदूरों से काम लेना और सभी तकनीकी मानकों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई दुर्घटना होती है, तो ठेकेदार, साइट इंजीनियर और निगरानी अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है— क्या इन नियमों की कोई कीमत नहीं बची? या फिर सब कुछ जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? रमजान के दौरान बिजली कटौती ने इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। धार्मिक भावनाओं और आम जरूरतों की अनदेखी कर जिस तरह से बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है, वह जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। बिजली विभाग की चुप्पी और नगर पालिका की निष्क्रियता लोगों के शक को और गहरा कर रही है।

अब क्षेत्रीय नागरिकों और श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर मांग उठाई है— तत्काल संयुक्त निरीक्षण हो, दोषी ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई हो, और सुरक्षा उपकरणों के बिना कार्य पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही, पहले हुए हादसों में मृत मजदूरों के परिवारों को न्याय और मुआवजा दिया जाए, और जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई की जाए। धनपुरी-बुढार रोड पर चल रहा यह कार्य अब केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सिस्टम की सच्चाई का आईना बन चुका है। यहां हर दिन मजदूर मौत से खेल रहे हैं और जनता अंधेरे में जीने को मजबूर है। अब देखना यह है—क्या प्रशासन जागेगा, या फिर एक और हादसे के बाद वही घिसी-पिटी संवेदनाएं और खोखले वादे दोहराए जाएंगे? क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ बिजली या काम का नहीं है—यह सवाल है इंसानी जान, जिम्मेदारी और व्यवस्था की असली नीयत का।

इनका कहना है

1.ठेकेदार से वर्जन लीजिए

सुश्री पूजा बुनकर
मुख्य नगर पालिका अधिकारी

बिजली कटेगी इसकी सूचना मोबाइल पर पूर्व मे दी गई थी, अब लाइट नही आ रही है तो आप ऊपर बाते कीजिए, ठेकेदार 3बजे से 5बजे तक का समय लिया है।

ए.ई. सुभास सेन बुढ़ार

33केवी लाइन काटने का अधिकार हमारे पास नही है आप ए ई साहब से बात कीजिए ।

अजीत श्रीवास्तव
जे ई विधुत मंडल धनपुरी

आरकेटीसी की मनमानी पर फूटा श्रमिकों का गुस्सा

▶ 3 दिन का अल्टीमेटम, नहीं माने तो ठप होगा उत्पादन और जाम होंगे पहिए

नवभारत, शहडोल। धनपुरी,अमलाई ओसीएम क्षेत्र में आरकेटीसी कंपनी के खिलाफ श्रमिकों का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर आने को तैयार है। अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन (ABAKMU) ने प्रबंधन को सीधी और कड़ी चेतावनी देते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम थमा दिया है। यूनियन ने दो टूक कहा है कि यदि तय समयसीमा के भीतर श्रमिकों की जायज मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो हड़ताल, काम बंद, उत्पादन ठप और चक्का जाम जैसे उग्र आंदोलन शुरू कर दिए जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

यूनियन के पदाधिकारियों ने ऋग्ञ्ष्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कंपनी लगातार श्रमिक विरोधी रवैया अपनाते हुए मजदूरों के अधिकारों का खुला उल्लंघन कर रही है। पहले भी कई बार पत्राचार और हड़ताल नोटिस दिए गए, लेकिन प्रबंधन ने हर बार उन्हें नजरअंदाज कर अपनी मनमानी जारी रखी। इससे मजदूरों में आक्रोश अब चरम पर पहुंच चुका है। यूनियन ने साफ तौर पर मांग रखी है कि पुराने और अनुभवी चेनजिंग पाथ के कर्मचारियों को तत्काल ऋग्ञ्ष्ट में पुन: रोजगार दिया जाए, जिन्हें सुनियोजित तरीके से बाहर किया गया है। साथ ही सभी कार्यरत श्रमिकों का 'बी-फॉर्म' भरवाकर उनकी सेवा को वैधानिक सुरक्षा दी जाए। मजदूरों का कहना है कि बिना दस्तावेजों के काम करवाना सीधे-सीधे श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाना है।

इसके अलावा सभी कर्मचारियों का एचपीसी टेस्ट कराए जाने और वेतन भुगतान को पूरी तरह बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की मांग भी उठाई गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की हेराफेरी पर रोक लगे। यूनियन ने ऋग्ञ्ष्ट द्वारा निकाले गए 8 कर्मचारियों को तत्काल बहाल करने और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है। सबसे चौंकाने वाला आरोप कोयले के अवैध परिवहन को लेकर लगाया गया है। यूनियन का कहना है कि कंपनी के भीतर अवैध गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। ऐसे में अवैध परिवहन में शामिल कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई और सभी मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाना जरूरी है। यूनियन ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो अमलाई क्षेत्र में हालात बेकाबू हो सकते हैं। हड़ताल, उत्पादन ठप और चक्का जाम से पूरा इलाका प्रभावित होगा।

गौ सम्मान आव्हान अभियान को लेकर बैठक आयोजित

नवभारत,शहडोल । गौ सम्मान आवाहन अभियान जो कि पूरे भारतवर्ष में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गौ माता के लिए केंद्रीय कानून बनाने एवं पूरे भारत से गौ हत्या समाप्त हो इस हेतु चलाए जा रहा है। इसके संदर्भ में आज शहडोल घरौला मोहल्ला वार्ड न. 19 में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहडोल के नंदी गौ सेवा धाम की टीम और कई गौ भक्त व गौ प्रेमी जन उपस्थित रहे। बैठक में मध्य प्रदेश प्रभारी द्वारा बताया गया यह अभियान पूरे भारत के सभी राज्य, सभी जिलों व तहसीलों में चलाया जा रहा है। जिसमें भारत के सभी मूर्धन्य सन्तो द्वारा 27 अप्रैल 2026 को देश की 5000 से अधिक तहसीलों में एक साथ, एक ही समय प्रार्थना पत्र तहसीलदार के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिले। यह अभियान पूर्ण संवैधानिक रूप से डेढ़ वर्ष तक चलेगा ।इस अभियान में प्रत्येक तहसील से 10000 हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य रखा गया है एवं 27 अप्रैल 2026 को को सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है।

इंजी . राकेश पाण्डेय जिला अध्यक्ष नियुक्त

▶ मप्र प्रगतिशील ब्राम्हण महासभा की बैठक आयोजित

नवभारत,शहडोल । सबसे प्राचीन जीवंत विप्र संगठन मप्र प्रगतिशील ब्राम्हण महासभा की बुधवार बैठक में इंजीनियर राकेश पाण्डेय क़ो शहडोल जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया. महासभा के प्रेरणा पुरुष पूर्व सीनियर एडवोकेट ब्रम्हालीन आदर्शमुनी त्रिवेदी के तेलचित्र पर नमन करके आशीर्वाद ग्रहण किया. इस अवसर पर एड. आशीष त्रिवेदी (अध्यक्ष जूनियर लायर्स एसोसिएशन) एड प्रशांत

अवस्थी (उपाध्यक्ष हाइकोर्ट बार एशोसिएशन) अखिलेश दीक्षित (भाजपा संभागीय मिडिया प्रभारी सहकारिता), रत्नेश मिश्रा(शिक्षक कर्मचारी संघ), एड ब्रजेश दुबे(प्रमुख कांग्रेस लीगल सेल जबलपुर) प्रवीण तिवारी पल्ली,एड असीम त्रिवेदी,जितेंद्र तिवारी, ने परशुराम पट्टीका, पुष्पहार, मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया गया।

तजुर्बा और खिदमत का इनाम, हाजी सरवर अली बने हज कमेटी के सरपरस्त

नवभारत, शहडोल। जिला हज कमेटी शहडोल की जानिब से एक अहम और काबिल-ए-तारीफ फैसला सामने आया है, जिसमें जिला अध्यक्ष सैयद जियाउल इस्लाम ने हाजी सरवर अली साहब को कमेटी का सरपरस्त (संरक्षक) मुक़र्रर किया है। इस नियुक्ति को महज एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि खिदमत-ए-खल्क के जज़्बे को दिया गया सम्मान माना जा रहा है।

हाजी सरवर अली साहब का नाम शहडोल सहित आसपास के इलाकों में बेहद अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। वे लंबे अरसे से हज पर जाने वाले जायरीन की खिदमत में पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ जुटे हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ यात्रियों को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई, बल्कि ट्रेनिंग,

रहनुमाई और हर मुमकिन मदद के जरिए उनकी सफर-ए-हज को आसान, सुरक्षित और मुकम्मल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी सादगी, तजुर्बा और खिदमत का जज़्बा उन्हें समाज में एक खास मुकाम दिलाता है ।जानकारी के मुताबिक, हाजी सरवर अली साहब वर्षों से जायरीन को हज के अरकान, दस्तावेजी प्रक्रिया, सफर की तैयारी और वहां के इंतजामात के बारे में बारीकी से मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। उनकी इसी लगन, ईमानदारी और बेहतरीन सेवाओं को देखते हुए जिला हज कमेटी ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। जैसे ही उनकी नियुक्ति की खबर सामने आई, मुस्लिम समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए हाजी सरवर अली साहब को दिल से मुबारकबाद पेश की। समाज के गणमान्य लोगों का मानना है कि उनके अनुभव, ईमानदारी और सेवाभाव से कमेटी को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। लोगों ने दुआ की कि अल्लाह तआला उन्हें अच्छी सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि वे इसी तरह जायरीन की खिदमत करते रहें और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाते रहें ।यह नियुक्ति इस बात का साफ पैगाम देती है कि समाज में खामोशी से और ईमानदारी से काम करने वालों की मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाती है और उन्हें उनका हक मिलता है।

100 दिवसीय जल गंगा संवर्धन अभियान आज से

नवभारत,शहडोल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 19 मार्च 2026 को भारतीय नववर्ष प्रतिपदा (गुड़ी पड़वा) के अवसर पर उज्जैन स्थित शिप्रा नदी तट से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया जाएगा ।कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशन में 19 मार्च से प्रारंभ होने वाले इस अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जिले की सभी जनपद पंचायतों के माध्यम से जल गंगा सवंर्धन अभियान सरकार एवं जनभागीदारी से आयोजित किए जाएंगे।

जल गंगा संवर्धन अभियान 100 दिवसीय जन-अभियान है, जिसका उद्देश्य जिले की नदियों, तालाबों, कुओं एवं बावड़ियों का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं साफ-सफाई सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत अधिक से अधिक जल संरचनाओं के पुनर्जीवन एवं सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में भू-जल स्तर में सुधार, जल अभाव वाले क्षेत्रों में राहत प्रदान करना, वर्षा जल का संचयन बढ़ाना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना शामिल है। अभियान के अंतर्गत नदियों, तालाबों, कुओं एवं बावड़ियों का गहरीकरण एवं कायाकल्प, सूखी नदियों का पुनर्जीवन, चेक डैम एवं स्टॉप डैम का निर्माण एवं मरम्मत, जल संरचनाओं के आसपास वृक्षारोपण एवं ग्रीन बेल्ट विकसित करना तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना जैसी गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। जल ही जीवन है के संकल्प के साथ जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन का एक व्यापक प्रयास है।

शहडोल संभाग में प्रगतिरत विकास कार्यों को कराएं समय-सीमा में पूर्ण : कमिश्नर

अनुमति के पश्चात ही ठेकेदारों से कराएं विकास कार्य : कमिश्नर

विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण कार्य सत्र प्रारंभ होने से पूर्व कराएं पूर्ण

नवभारत,शहडोल । कमिश्नर शहडोल संभाग सुरभि गुप्ता ने कमिश्नर कार्यालय के अमरकंटक सभाकक्ष में शहडोल संभाग में विभाग द्वारा किये जा रहे निमार्णधीन विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कमिश्नर ने अधिकारियो को निर्देश शहडोल संभाग में प्रगतिरत विकास कार्यो को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण कराएं एवं जिन ठेकेदारो द्वारा कार्यों में रूचि नही ली जा रही उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए ब्लैकलिस्ट करें। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में किसी तरह की समस्या है अथवा किसी विभाग से समन्वय की आवश्यकता है तो समन्वय कर उनका निराकरण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर विकास कार्य करें तथा आपस में सूचित करके काम प्रारंभ कराएं जिससे सार्वजनिक संपत्ति को हानि नहीं हो।

कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिए कि शहडोल संभाग में संचालित विद्यालयो एवं ऑगनवाड़ी केंद्रो में शुद्व एवं स्वच्छ पेयजल, बिजली जैसी अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सक्षम ऑगनवाड़ी केंद्रो में बच्चो को शुद्व एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उददेश्य से आर.ओ. तथा टीव्ही लगाई जानी है जिसके लिए विद्युत कनेक्शन आवश्यक है। शासन द्वारा विद्युत मंडल को विद्युत कनेक्शन हेतु राशि भी प्रदाय की गई है। जिन विद्यालयो के लिए राषि उपलब्ध कराई गई है वहाँ विद्युत कनेक्शन शीघ्र पूरा किया जाए। कमिश्नर ने पीएम जनमन एवं धरती आबा कार्यक्रम के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देष दिए कि ये सभी कार्य समय-सीमा में पूरे किये जाएं। विद्युत देयक एवं स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य अभियंता ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्रो में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद पूरा कर लिया गया है अब ग्रामीण क्षेत्रो में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्युतदेयक एवं स्मार्ट मीटर से संबंधित षिकायतो में कमी आई है। बैठक में कमिश्नर द्वारा संभाग के तीनो जिलो में नये सब स्टेषन निर्माण, फीडर सेपरेषन, 33 केव्ही लाइन बिछाने का कार्य तथा पॉवर स्टेशन निर्माण एवं उनके प्रारंभ होने की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि शहडोल संभाग के विद्युतविहीन ग्रामो की सूची भी उपलब्ध कराएं। कमिश्नर ने कहा कि शहडोल संभाग के विद्यालयो एवं छात्रावासो में किये जा रहे निर्माण कार्यों को विद्यालय सत्र प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण कराएं जिससे नये सत्र में आने वाले विद्यार्थियो को सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकें। कमिश्नर ने आरडीएसएस परियोजना अंतर्गत आंवटित कार्य, शहडोल-उमरिया मार्ग, धरती आबा के तहत किये जा रहे विकास कार्य, मध्यप्रदेष ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत किये जा रहे निमार्ण कार्य, पीएम जनमन के तहत प्रस्तावित मार्ग, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियो को दिए। बैठक में आयुक्त शहडोल संभाग द्वारा ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, एमपीआरडीसी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भवन निर्माण, कारपोरेशन, ब्रिज कारपोरेषन तथा जनजातीय कार्य विभाग के कार्यों की विस्तार से कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागो के संभागीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।

लापरवाही | तो क्या हिस्सा लेकर किस्सा खत्म करने मे लगे जिम्मेदार, जिला पंचायत के आदेश का ब्योहारी सीईओ नहीं कर रही पालन

महिना बीत गया जांच शुरु नहीं, एक सप्ताह में देना था प्रतिवेदन

नवभारत, ब्योहारी। सरकारी नियमों का पालन करने और व्यवस्था संचालित करने के लिए पदस्थ अमला आज इतना निष्क्रिय और स्वेच्छचारी हो चुका है कि वह अपने ही अधिकारियों के आदेश को ठेंगा दिखा रहा है।

सरकारी दफ्तरों का अनुशासन लगभग छिन्न-भिन्न हो चका है। न तो फील्ड का मौका मुआयना किया जा रहा है और न ही कार्यालय में फाइलों पर निर्णय लिया जा रहा है। शिकायतों का अम्बार लगा हुआ है, समस्याएं बढ़ती जा रहीं है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ब्योहारी जनपद अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत पापोढ की सीतेश त्रिवेदी बसपा जिला उपाध्यक्ष ने सरपंच, सचिव के विरुद्ध जिला पंचायत शहडोल मे 4 बिन्दुओ मे शिकायत की थी। शिकायत को संज्ञान मे लेते हुए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल ने दिनांक 04/02/2026 को पत्र क्रमांक /जि. प./शिकायत /

2026/364 सीईओ ब्योहारी को भेजकर एक सप्ताह मे जांच प्रतिवेदन चाहा गया था किन्तु 1 माह का समय बीतजाने के बाद भी सीईओ द्वारा जांच टीम गठित नहीं की गयी और न ही उक्त शिकायत की जांच ही कराई गयी। सायद सीईओ के लिये जिला पंचायत का आदेश मायने नहीं रखता है। ज्ञात हो की ग्राम पंचायत पपोढ मे नाली निर्माण और पीसीसी सड़क निर्माण के नाम पर 2 साल पूर्व राशि का आहरण कर लिया गया है किन्तु निर्माण कार्यों का धरातल मे कंही रता पता नहीं है।

सीईओ पर संरक्षण का आरोप शिकायतकर्ता का आरोप है कि ब्योहारी सीईओ के संरक्षण मे पंचायतो मे भ्रस्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। गांधी के फेर मे शिकायत को दबाया जाता है। जांच के नाम पर जनपद मे वसूली अभियान चल रहा है जिसका जीता जागता सबूत ग्राम पंचायत पापोढ का है जंहा निर्माण कार्यों के नाम पर राशि का तो आहरण कर लिया गया है और निर्माण कार्यों का कंही धरातल मे रता पता नहीं है। शिकायत पर कार्यवाही तो दूर जांच तक नहीं की जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो ये सब सीईओ की मिली भगत से हो रहा हो।

घूस की लगी बीमारी तो भाड़ में जाये जिम्मेदारी

विडंबना इस बात की है कि जिस पर पंचायतो मे हो रहे भ्रस्टाचार पर रोक लगाने का जिम्मा है वही ज़ब संलिप्त हो तो फिर उनसे न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है। जनपद मे अधिकारी गाँधी के चक्कर मे अपने जिम्मेदारी से मुँह मोड़ रहे है। शिकायतकर्ता ने जिले के आला अधिकारियो से इसे संज्ञान मे लेकर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है।

सांसद हिमाद्री सिंह करेंगी सूर्य उपासना कार्यक्रम का शुभारंभ

नवभारत, शहडोल । सृष्टि आरंभ दिवस, वर्ष

प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ अवसर पर सूर्य उपासना कार्यक्रम का आयोजन शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह के मुख्य आतिथ्य में जनपद पंचायत सोहागपुर के सभागार में 19 मार्च 2026 को प्रात: 10 बजे से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में संस्कृति विभाग भोपाल के कलाकारों द्वारा नाट्य प्रस्तुति सम्राट विक्रमादित्य का मंचन किया जाएगा।

एचपीवी टीकाकरण कराएं और बेटियो का भविष्य सुरक्षित बनाएं

नवभारत, शहडोल । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने शहडोल जिले के नागरिको से अपील करते हुए कहा है कि 28 फरवरी से 31 मई 2026 तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान में अपने 14 से 15 वर्षीय बेटियो को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी का टीका अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए शहडोल जिले के शासकीय स्वास्थ्य केंद्रो में एचपीवी का टीका नि:शुल्क लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि एचपीवी वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का अत्यंत कारगर और प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की भ्रांतियों से दूर रहें और अपनी 14 से 15 वर्षीय बच्चियो को एचपीवी का जीवनरक्षक टीका अवश्य लगवाएं।

कार्यालय नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक-1647 / न.परि. / भण्डार / 2025-26 जयसिंहनगर दिनांक, :- 06/03/2026

ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https:www.gem.gov.in पर देखा जा सकता है :- अनुसूची

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4
1.	GEM/2026/B/7319794	Special Tools (Deepwell Hand Pumps Components) as per IS 15500 (Q3)	23/03/2026
2.	GEM/2026/B/7311272	LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme -II) (Q2)	23/03/2026

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन आनलाइन https:www.gem.gov.in की वेबसाईट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र मे प्रकाशन नही किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.)